हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 95 देहरादून, शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

फेसबुक की मदद से गड्ढामुक्त होंगी दून की सड़कें, जिलाधिकारी सोनिका का अभियान 3

अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन एवं टोकन व्यवस्था शुरू होगी : मुख्यमंत्री

स्वास्थ्य संबंधी कार्डों की सही मॉनिटरिंग के लिए भी तैयार किया जाए प्लेटफॉर्म

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 30 सितंबर , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि अस्पतालों में मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाईनों में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं टोकन की व्यवस्था के लिए सिस्टम विकसित किया जाए। टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाईन नम्बर 104 को जन जगारूकता के लिए व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। उत्तराखण्ड को जल्द क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए क्षय रोगियों को गोद लेने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रेरित किया जाए, अगर किसी कार्य से लोग मन से जुड़ते हैं, तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जारी होने वाले आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी होने वाले कार्ड तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्डों की सही मॉनिटरिंग के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए।

■ टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाईन नम्बर 104 का व्यापक प्रचार किया जाए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अभिनव पहल की जरूरत हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डॉक्टरों को प्रेरित किया जाए। ब्लॉक एवं तहसील स्तर तक स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं। ऐसी व्यवस्था की जाए कि नवजात शिशु के अस्पताल में जन्म होने पर उनके जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से ही निर्गत हों।

■ त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत बरती जाए विशेष सतर्कता

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में स्वच्छता की उचित व्यवस्था हो। मरीजों को अस्पतालों में गुणवत्तायुक्त भोजन मिले। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल के बाद वायरल, डेंगू एवं मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है, इससे निपटने के लिए अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जाए।

■ तनिर्माण कार्यों में विलंब के लिए जिम्मेदारी हो तय

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिन निर्माण कार्यों में विलंब हो रहा है, सबंधित कार्यदाई एजेंसियों के खिलाफ सख्त रूख अपनाया जाए एवं संबंधितों जिम्मेदारी भी तय की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब होने से लागत में भी वृद्धि होती है। उत्तराखण्ड को 2025 तक ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के लिए सभी विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रतिमाह बैठक की जाए।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में रोगी पंजीकरण शुल्क की समान व्यवस्था की जाए। ब्लॉक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को भी ध्यान में रखना होगा।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राज्य में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव अरूणेन्द्र चौहान, अमनदीप कौर, प्रभारी महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, प्रधानचार्य दून मेडिकल कॉलेज डॉ. आशुतोश सयाना, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. सरोज नैथानी एवं स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

नए CDS अनिल चौहान के पैतृक गांव गवांणा में जश्न, उत्तराखंड को एक और उपलब्धि

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 30 सितंबर , लेफ्टिनेंट जनरल (रि) अनिल चौहान को देश का सीडीएस नियुक्त किया गया है. अनिल चौहान के सीडीएस नियुक्त होते ही उत्तराखंड के लोगों का सीना एक बार फिर से गर्व से चौड़ा हो गया है. वहीं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के गांव गवांणा में भी लोग ढोल-दमाऊं की धुन पर झूमते दिखाई दिए।

गवांणा गांव में सुरेंद्र सिंह चौहान के घर 18 मई 1961 में जन्मे अनिल चौहान की प्रारंभिक पढ़ाई कलकत्ता सहित देश के अन्य राज्यों में हुई. अनिल और उनके परिवार की जड़े हमेशा ही उनके गांव में बसी रही. गांव में रहने वाले उनके चचरे भाई दर्शन सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके चाचा सुरेंद्र सिंह चौहान और उनके भाई सीडीएस अनिल चौहान गांव में होने वाले बार त्योहारों में जरूर गांव आते हैं. जब उन्हें पता चला उनके भाई अनिल देश के दूसरे सीडीएस बनाये गये हैं तो उन्होंने चाचा सुरेंद्र को फोन कर बधाई दी. उन्होंने बताया चाचा ने उन्हें अपने घर देहरादून भी बुलाया है. उनके भाई और बहन उनके घर जाएंगे... उत्तराखंड को जिस तरह से एक बार फिर पहाड़ के जांबाज़ बेटे की उपलब्धि ने गर्व करने का मौका दिया है वो बताता है कि आखिर क्यों देवभूमि को पीएम मोदी ने सैन्यधाम का नाम दिया है।

सिर्फ 500 रुपये प्रति रात में करें उत्तराखंड में जेल का दौरा, जानिए पूरी खबर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड में घूमने लायक कई जगह हैं। लेकिन इस बार उत्तराखंड आपके लिए कुछ नया टूर लेकर आया है।उत्तराखंड के हल्द्वानी में जेल प्रशासन लोगों को ₹बुरे कर्मं₹ से बचाने में मदद करने के लिए एक अनूठा विचार लेकर आया है - जेल में प्रति रात 500 रुपये के मामूली शुल्क पर।हल्द्वानी जेल 1903 में बनाया गया था और इसके एक हिस्से में छह स्टाफ क्वार्टर के साथ पुराने शस्त्रागार शामिल हैं, जो कि छोड़ दिया गया है, वर्तमान में ₹जेल के मेहमानों₹ को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जेल के उप जेल अधीक्षक सतीश सुखिजा ने बताया कि जेल को अक्सर वरिष्ठ अधिकारियों से ₹अनुशंसित व्यक्तियों₹ को जेल की बैरक में कुछ घंटे बिताने की अनुमति देने के ₹आदेश₹ मिलते हैं। इन ₹पर्यटक कैदियों₹ को जेल की वर्दी और जेल की रसोई में बना खाना दिया जाता है।

उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल में परिसर के एक परित्यक्त हिस्से को ₹पर्यटकों₹ के लिए आवास के रूप में बदलने के लिए काम चल रहा है, जो वास्तविक ₹जेल महसूस₹ की तलाश में हैं या जिन्हें ज्योतिषियों ने अपनी कुंडली में ₹बंधन योग₹ को दूर करने के लिए जेल में समय बिताने की सलाह दी है। कैद की अवधि की भविष्यवाणी करें।

₹ऐसे सभी मामले मुख्य रूप से उन लोगों के हैं जिनके ज्योतिषियों का अनुमान है कि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जेल की अवधि अपरिहार्य है। हमारे पास जेल के अंदर एक परित्यक्त हिस्सा है जिसे ऐसे 'कैदियों' को समायोजित करने के लिए एक डमी जेल के रूप में विकसित किया जा सकता है। 500 रुपये के मामूली शुल्क के लिए रात, "जेल अधिकारी ने कहा।

शहर के एक ज्योतिषी, मृत्युंजय ओझा ने कहा, ₹जब किसी की कुंडली या जन्म कुंडली में शनि और मंगल सहित तीन खगोलीय पिंड प्रतिकूल स्थिति में होते हैं, तो यह एक समीकरण बन जाता है जो भविष्यवाणी करता है कि व्यक्ति को कारावास से गुजरना पड़ सकता है। में ऐसी स्थिति में, हम आमतौर पर विषय को जेल में रात बिताने और कैदियों को भोजन उपलब्ध कराने की सलाह देते हैं ताकि ग्रहों की स्थिति के बुरे प्रभावों को दूर किया जा सके।

सुखिजा ने कहा, ₹मैंने पहले भी इस मामले के संबंध में जेल महानिरीक्षक के पास एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने (पुष्पक ज्योति) न केवल इसकी सराहना की बल्कि मुझे एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा।

क्या आप जानते हैं एक मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल

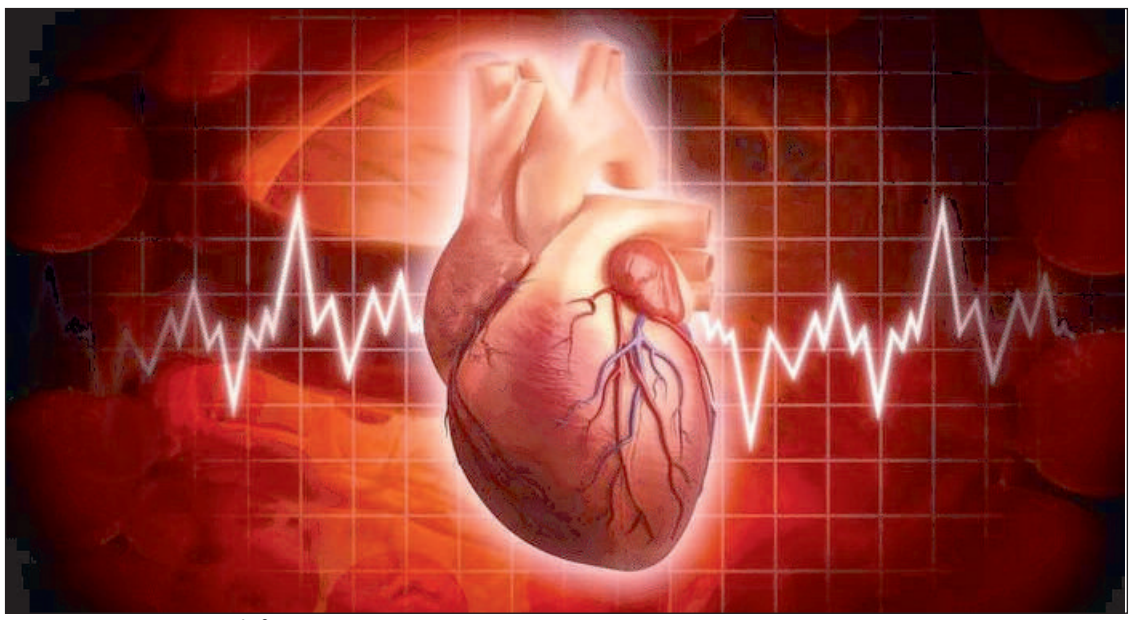

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 30 सितंबर ,हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग हृदय ही माना जाता है। हृदय का काम पूरी धमनियों के माध्यम से आक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को ऊतकों और शरीर के अन्य हिस्सों पम्प कर पहुंचाना है।

आजकल लोगों को हृदय संबंधी बिमारियां भी घेर रहीं है। आए दिन हृदयघात से लोगों की जान जाने की सूचना मिलती है। लेकिन आज भी लोगों को दिल से जुड़ी सामान्य जानकारी नहीं हैं।

1. क्या आप जानते हैं, आपका दिल एक मिनट में कितनी बार दड़कता है? नहीं, तो बता दें कि हम सबका दिल सामान्य तौर पर 60 से 100 बार एक मिनट में धड़कता है।

2 . अगर आपका दिल आपके शरीर से हटा भी दिया जाए तब भी यह धड़कता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल प्रभाव हमेशा सक्रिय रहते है।

3. डाक्टरों की मानें तो आपके दिल के लिए सबसे बेहतर चीज डार्क चाकलेट साबित हो सकती है। इसे खाने से हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं। हालांकि, डाक्टरों का कहना है कि हमें एक निश्चित मात्रा में ही इसे खाना चाहिए।

4. आमतौर पर हार्ट अटैक को ही लोग कार्डियक अरेस्ट मानते हैं। लेकिन, हार्टअटैक तब आता है जब अचानक ही हृदय की किसी मांसपेशी में खून का संचार बंद हो जाता है। हार्टअटैक में हृदय बाकी शरीर के हिस्सों को खून का संचार करता रहता है। वहीं, दूसरी ओर कार्डियक अरेस्ट में हृदय खून का संचार ही पूर्ण रूप से बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट में किसी भी हिस्से को खून नहीं पम्प होता है और सांस आनी भी बंद हो जाती है।

भक्ति में लीन 27 साल का युवक योग और ध्यान करने पहुंचा मंदाकिनी ग्लेशियर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बिहार के दरभंगा जिले के एक 27 वर्षीय व्यक्ति, जिसने ₹योग और ध्यान₹ करने के लिए लगभग एक सप्ताह पहले केदारनाथ मंदिर से 6 किमी की चढ़ाई की थी, उसको राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मंदाकिनी ग्लेशियर से बचाया। एसडीआरएफ की प्रवक्ता ललिता नेगी ने कहा, ₹पंकज कुमार नाम के व्यक्ति ने एक ऊंचाई वाले इलाके में ट्रेकिंग की थी। उसने बिना किसी भोजन के योग और ध्यान करने का प्रयास किया।₹मंगलवार को चोराबाड़ी ग्लेशियर जा रहे लोगों ने उसे कमजोर हालत में देखा और केदारनाथ लौटकर पुलिस को सूचना दी।बुधवार को हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम को उसकी तलाश के लिए इलाके में भेजा गया था. एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने कहा, ₹करीब 6 किमी के बहुत कठिन ट्रेक के बाद, टीम ने उन्हें एक चट्टान पर बैठे देखा। उनकी हालत वास्तव में खराब थी।₹उन्हें पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर भोजन और पानी दिया गया और वापस केदारनाथ लाया गया, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है।

मेडिकल फैकल्टी को मिलेगा 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता, डॉ0 धन सिंह रावत को बड़ी सफलता

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 30 सितम्बर , उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज अब फैकल्टी की समस्या से नहीं जूझेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत की पहल पर राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में नियमित एवं संविदा पर तैनात मेडिकल फैकल्टी को उनके वेतनमान के सापेक्ष 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है, जिसका शासनादेश शीघ्र जारी कर दिया जायेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों को आवश्यकतानुसार फैकल्टी मिल सकेगी।

प्रदेश सरकार सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के तहत पर्वतीय जनपदों के मेडिकल कॉलेजों में नियमित एवं संविदा पर तैनात मेडिकल फैकल्टीज को उनके वेतनमान के सापेक्ष 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता दिया जायेगा। जिससे फैकल्टी की कमी से जूझ रहे मेडिकल कॉलेजों को बड़ी राहत मिलेगी।

राज्य के पर्वतीय जनपदों में स्थित मेडिकल कॉलेज शुरू से ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भारी कमी से जूझ रहे हैं। यहां विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए हर बार साक्षात्कार तो किया जाता है, लेकिन सेलेक्शन के बावजूद अधिकतर विशेषज्ञ चिकित्सक इन कॉलेज में योगदान नहीं देते हैं। मेडिकल फैकल्टी की इसी कमी को दूर करने के लिये सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने एक नया विकल्प राज्य सरकार के समक्ष रखा। जिस पर उन्होंने श्रीनगर, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु मेडिकल फैकल्टी को वेतनमान के सापेक्ष 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा।

राज्य कैबिनेट ने डॉ0 रावत के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुये इसे सराहनीय पहल बताया। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विभागीय मंत्री डॉ0 रावत ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुये विभागीय अधिकारियों को शीघ्र शासनादेश जारी करने के निर्देश दे दिये हैं। जिसका शासनादेश शीघ्र जारी होने की उम्मीद है। राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मेडिकल फैकल्टी को मिलने वाला 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता मेडिकल टीचर्स डिफिसेंसी कॉम्पेन्सेटरी स्कीम के अंतर्गत दिया जायेगा। जिसके लिये संबंधित विभाग में एक कॉर्पस फंड बनाया जायेगा, जिसका संचालन संबंधित कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। मेडिकल फैकल्टी को 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता मिलने पर पूर्व में स्वीकृत 20 फीसदी डिफिकल्ट हिल एरिया एलाउंस देय नहीं होगा। विभाग को उम्मीद है कि इस नई पहल से पहाड़ के मेडिकल कॉलेजों में लम्बे समय से चली आ रही फैकल्टी की कमी दूर हो सकेगी।

देहरादून में अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के रूटीन निरीक्षण के डीएम सोनिका ने दिए निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 30 सिंतबर जिलाधिकारी/समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी सोनिका की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में अवस्थित अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के रूटीन निरीक्षण के साथ ही केन्द्रों पर मानकों का पालन करवाने एवं नियमानुसार व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी डॉयग्नोस्टिक सेंटर पर चिकित्सकों की बैठने का समय एवं जिस चिकित्सक का विवरण अनुमति में दर्शाये गए चिकित्सक निर्धारित समय पर उपस्थित है की भी जांच करें। साथ ही नवीन तथा नवीनीकरण की आवेदनों के संबंध में निरीक्षण के दौरान सभी मानकों को बारिकी से जांच के उपरान्त ही अनुमति हेतु समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें।

बैठक में संयुक्त निदेशक विधि जी.सी पंचोली, डीजीसी जी.पी रतूड़ी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 मनोज उप्रेती, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 दिनेश चैहान, डॉ0 ममता बहुगुणा, सहायक निदेशक सूचना बीसी नेगी, समर्पित संस्था से कमला जेसवाल सहित संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।

फेसबुक की मदद से गड्ढामुक्त होंगी दून की सड़कें, जिलाधिकारी सोनिका का अभियान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 30 सितंबर , हाल ही में हुयी बरसात के कारण देहरादून की कई सड़के खस्ताहाल हो चुकी हैं.. राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के तौर पर पहचान दिलाने के लिए वैसे तो काम किया जा रहा है, लेकिन यहां की खस्ताहाल सड़कें इसकी छवि पर पलीता लगा रही हैं. दून की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अब यहां की जिलाधिकारी सोनिका ने मुहिम शुरू की है. फेसबुक पर जिलाधिकारी 'पैचलेस रोड्स ऑफ देहरादून' पेज के साथ अभियान चला रही हैं. अगर किसी नागरिक के घर के आस-पास की सड़कों पर गड्ढे हैं, तो वो जिला प्रशासन को इस समस्या की जानकारी दे सकते हैं.लोगों के मुताबिक बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भर जाता है जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण बनता है. सड़क ख़राब होने के कारण कई हादसे हो चुके हैं..सड़कों पर गड्ढे और खराब पैचवर्क वाहन चालकों के लिए भी मुश्किलें खड़ी करते हैं.जिलाधिकारी सोनिका ने इस बारे में जानकारी दी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी नागरिक गड्ढों वाली सड़कों से जुड़ी जानकारी जिला प्रशासन को दे सकता है. इस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सड़क को दुरुस्त किया जाएगा.जिला प्रशासन की फेसबुक के माध्यम से चलाई जा रही इस मुहिम से लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं. सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है. तो वहीं, कई लोग धरातल पर काम मांग भी रहे हैं. फेसबुक पेज के अलावा पोर्टल (smartcity-dehradun.uk.gov.in) और मेल आईडी (dm-deh-ua@nic.in)के माध्यम से भी सड़कों से जुड़ी अपनी परेशानी से प्रशासन को अवगत कराया जा सकता है.

पहले राज्य की बेटियों का हक दिलवाओ फिर परीक्षा करवाओ : भुवन कापड़ी

फ़िरोज़ आलम की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 30 सितंबर। उत्तराखंड के खटीमा से विधायक और उप नेता विपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश के मौजूदा हालात पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भर्ती परीक्षाओं और महिलाओ के आरक्षण पर भी कापड़ी ने अपना और पार्टी का पक्ष साफ़ किया है। जानकारी देते हुए कापड़ी बताते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड महिलाओं को राज्य प्रशासनिक सेवाओं में दिए जा रहे 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगाई है। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि राज्य PCS परीक्षा में महिलाओं के लिए दोबारा कट ऑफ जारी करी जाए जिसमें बाहरी राज्यों की महिलाओं को भी 30% आरक्षण के कोटे में शामिल किया जाए।

इस क्रमः में दिनांक 22 सितम्बर को हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लोक सेवा आयोग ने बाहरी राज्यों की सभी महिलाओं को परीक्षा में शामिल करते हुए नया परीक्षा परिणाम जारी कर दिया, जिसमें बाहरी राज्यों की प्रत्येक महिला को मुख्य परीक्षा देने का मौका दे दिया गया है।लेकिन यह लोक सेवा आयोग का दोहरा रवैया है कि जहां एक ओर आयोग वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, ज्यूडिशियल सेवाओं की परीक्षाओं में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है वहीं दूसरी ओर आयोग आरक्षण के मुद्दे से सबसे ज्यादा प्रभावित ₹राज्य PCS मुख्य परीक्षा₹ करवाने पर अड़ा हुआ है ! आयोग की इस हठधर्मिता के कारण आज राज्य की बेटियों का भविष्य अधर में लटक चुका है।दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार पिछले दो महीने से स्थानीय महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में ₹अध्यादेश₹ लाने एवं सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने के वादे करते रही, इस बीच सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आयोग ने बाहरी राज्य की लड़कियों को स्थानीय महिलाओं के लिए निर्धारित कोटे में शामिल कर दिया है।

इस प्रकार स्थानीय महिलाओं के अधिकारो से हुए कुठाराघात से राज्य की प्रत्येक महिला अभ्यर्थी निराश है,एवं राज्य की आधी आबादी अपने हितों की रक्षा हेतु सरकार की ओर देख रही है। आयोग द्वारा सरकार को महिला आरक्षण में प्रयास करने का मौका दिए बिना परीक्षा कराने से उन उत्तराखंड की महिलाओं के साथ भी अन्याय होगा जो अपने हकों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है और सरकारी प्रतिनिधियों से मिलकर हर यथासंभव प्रयास कर रही हैं।

राज्य की स्थानीय महिलाओं की एक ही मांग है कि राज्य सरकार वास्तविक रूप में राज्य की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़े, एवं जब तक सरकार, स्थानीय महिलाओं हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित नहीं कर लेती तब तक बाहरी महिलाओ को किसी भी स्थिति में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित ना करे। इसके अतिरिक्त जब तक राज्य की बेटियों के पक्ष में सरकार 30% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित नहीं कर लेती, तब तक मुख्य परीक्षा ना करवाई जाए।

राज्य निर्माण आंदोलन में प्रदेश की मातृशक्ति अग्रणी भूमिका को सरकार हमेशा याद रखना होगा यही शहीद आंदोलनकारी महिलाओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चुनाव के समय आधी आबादी से किये वादे पूरे करने का राज्य की महिला अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है।

पत्नी से जबरदस्ती भी रेप ही है , सुरक्षित गर्भपात कराने का है अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 30 सितंबर , सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर कहा है कि अविवाहित और विवाहित महिलाओं के बीच भेदभाद नहीं हो सकता है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार(29 सितंबर) को कहा कि सभी महिलाएँ सुरक्षित गर्भपात कराने का अधिकार रखती हैं। वो चाहे अविवाहित हों या विवाहित।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही महिलाएं

दरअसल अभी तक सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही 20 सप्ताह से अधिक और 24 हफ्ते से कम समय तक ही गर्भपात का अधिकार था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अविवाहित महिलाओं को भी इस समय सीमा तक गर्भपात कराने का अधिकार होगा। अदालत ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है। यह फैसला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनाया है।

अदालत ने कहा कि सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही अनुमति मिलना अविवाहित महिला के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं जिनका मैरिटल रेप हुआ है, वे भी अबॉर्शन करा सकेंगी। विवाहित महिलाओं को भी 20-24 हफ्ते के गर्भ को अबार्ट कराने की अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी महिलाएं जो लिव-इन रिलेशनशिप से इतर प्रेग्नेंट हुई हैं, उन्हें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स से बाहर करना असंवैधानिक है। अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत रेप का मतलब मैरिटल रेप समेत होना चाहिए।

अदालत ने आगे कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद एक स्टीरियोटाइप को कायम रखता है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन गतिविधियों में लिप्त होती हैं। किसी महिला की वैवाहिक स्थिति के आधार पर उससे अबॉर्शन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सिंगल और अविवाहित महिलाओं को प्रेग्नेंसी के 24 हफ्ते तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत अबॉर्शन का अधिकार है।

उत्तराखंड से बने देश के दूसरे सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया। पौड़ी गढ़वाल जिले के खिर्सू प्रखंड के रामपुर ग्राम सभा के गवाना गांव के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) चौहान सीडीएस का पद संभालने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। उनके पूर्ववर्ती, जनरल बिपिन रावत, देश के पहले सीडीएस, पौड़ी गढ़वाल जिले के द्वारीखाल ब्लॉक से थे। 8 दिसंबर, 2021 को तमिलनाडु में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी।कर्नल अजय कोठियाल (सेवानिवृत्त) ने कहा, ₹यह उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जनरल रावत की तरह एक मूल निवासी हैं। दोनों एक ही जिले, एक ही राज्य और एक ही 11 गोरखा रेजिमेंट के हैं।₹मई 2021 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद से, चौहान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में एक शीर्ष पद के अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। न्यूज नेटवर्क

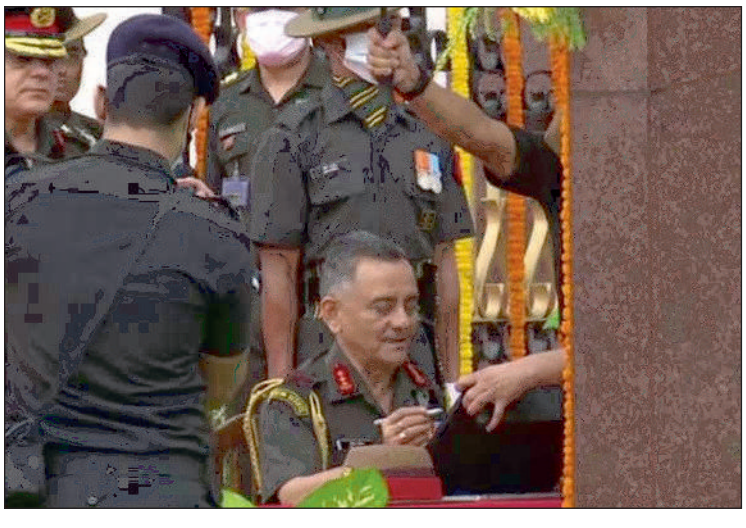

देहरादून में चलाया जागरूकता अभियान बाजार में न बेचें नई डीपीसी आर्मी ड्रेस

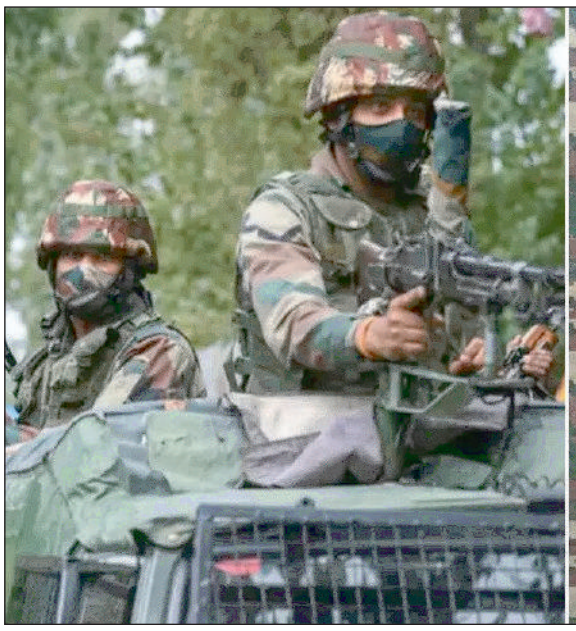

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

भारतीय सेना ने देहरादून के गढ़ी कैंट, डकरा बाजार और पलटन बाजार क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया, ताकि दुकानदारों को जागरूक किया जा सके कि डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट (डीपीसी) ड्रेस किसी भी व्यक्ति को नहीं बेची जानी चाहिए, क्योंकि यह अनधिकृत और गैरकानूनी है।दो दिवसीय अभियान 25 सितंबर को शुरू किया गया था और इसी तरह का अभियान जोशीमठ में भी चलाया गया था, रक्षा बलों की केंद्रीय कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने कहा।सेना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीपीसी की वर्दी केवल सेवा कर्मियों के लिए अधिकृत है और सेवारत संवर्ग के बाहर पोशाक पहनना अनधिकृत है।सैन्य पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ दुकानदारों को किसी भी पैटर्न की लड़ाकू वर्दी अनधिकृत व्यक्तियों को नहीं बेचने का आह्वान किया। टीम ने दुकानों का दौरा किया और दुकानदारों को दिशा-निर्देशों और परिणामों के बारे में सूचित किया कि क्या वे किसी को डीपीसी ड्रेस बेचते हुए पाए गए।ऐसी इनपुट थी कि डीपीसी वर्दी के समान पैटर्न वाले कपड़े बेचे जा रहे थे, जिसके बाद दुकानदारों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अधिकारी ने कहा कि डीपीसी ड्रेस का अनावरण इस साल की शुरुआत में जनवरी में किया गया था और इसका भारतीय सेना ने पेटेंट कराया है।

मतगणना के दौरान हरिद्वार-रुड़की में कार्यकर्ताओं ने किया पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार। हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान हरिद्वार के बहादराबाद और रुड़की के मंगलौर में बवाल हो गया। जिला पंचायत सीट टिकौला पर दोबारा मतगणना को लेकर आसपा समर्थकों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। हमले में एक चौकी इंचार्ज समेत छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर पथराव करने वालों को दूर तक खदेड़ा। वहीं, पुलिस ने मौके से 36 बाइक और कई लोगों को हिरासत में लिया है। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पथराव की सूचना पर एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिला पंचायत सीट टिकौला पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने बसपा नेता राजेंद्र चौधरी के भतीजे अंशुल चौधरी थे। परिणाम आने के बाद

अंशुल चौधरी के 275 वोटों से जीतने की घोषणा की गई। इस पर सुरेंद्र कुमार का आरोप था कि पहले उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया था और रीकाउंटिंग की मांग नहीं सुनी गई। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को दी।

करीब चार बजे वह समर्थकों के साथ मतगणना स्थल गुड़ मंडी पर पहुंचे और अंदर घुसने का प्रयास किया लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस पर वह गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद चंद्रशेखर और महक सिंह ने समर्थकों को संबोधित करते हुए मामले में निर्वाचन आयोग से शिकायत करने और कोर्ट की शरण लेकर न्याय दिलाने की बात कही फिर दोनों नेता चले गए लेकिन समर्थक काफी देर तक डटे रहे।

इसी बीच पुलिसकर्मियों ने उनके नेताओं के चले जाने के बाद जगह खाली करने को कहा तो नोकझोंक शुरू हुई। तभी समर्थकों में से किसी ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी होने पर पुलिसकर्मी भागकर गेट के भीतर घुस गए फिर हेलमेट पहनकर बाहर आए और लाठीचार्ज करते हुए दूर तक खदेड़ा। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद पुलिस ने मौके से 36 बाइकों को ट्रक में भर लिया। साथ ही छह लोगों को हिरासत में लिया।

घायल पुलिस चौकी इंचार्ज समेत घायल सभी पुलिसकर्मियों को पहले सीएचसी मंगलौर और फिर सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया। एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उधर, एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं, बहादराबाद में रोहालकी स्थित राष्ट्रीय इंटर कालेज में चल रही मतगणना में आबिदपुर-भगतनपुर पंचायत सीट पर प्रधान पद के लिए दोबारा मतगणना कराने को लेकर बृहस्पतिवार की रात विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मतदान केंद्र के बाहर खड़े सैकड़ों समर्थकों ने बैरिकेंडिंग तोड़ते हुए पथराव कर दिया।

जाने किसके वजह से लग रहा है राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की चपत

उत्तराखण्ड परिवहन
उत्तराखंड परिवहन विभाग भर्ती

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

चारधाम यात्रा में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से कई यात्री वाहन श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे हैं। ये वाहन बिना टैक्स चुकाए चारधाम यात्रा पर निकल रहे हैं। जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही पहाड़ी रास्तों की सही जानकारी न होने से यात्रियों की जान भी खतरे में है। ऐसे में परिवहन विभाग की लापरवाही से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।

हरिद्वार में यात्रा व्यवसायियों की शिकायत पर एआरटीओ रश्मि पंत ने भूपतवाला के एक आश्रम में दो दर्जन से अधिक वाहन जब्त किए. यात्रा व्यवसायी हरिद्वार में आरटीओ अधिकारी की नियुक्ति व स्थानीय यात्रा व्यवसायियों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। उधर, मौके पर पहुंची एआरटीओ रश्मि पंत ने कार्रवाई की बात कही है.

ट्रैवल बिजनेसमैन गिरीश भाटिया का कहना है कि हम लगातार कई बार

एआरटीओ के सभी उच्चाधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। जिससे हम जैसे ट्रैवल बिजनेसमैन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाहरी राज्यों की कारें यात्रियों को बिना टैक्स दिए सस्ते दरों पर चारधाम यात्रा प्रदान करती हैं। जिसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। एआरटीओ रश्मि पंत ने कहा कि हमारे द्वारा समय-समय पर लगातार कार्रवाई की जाती रही है. सूचना मिलते ही कई वाहनों को सीज कर दिया गया है।

सावधान : ऑनलाइन नौकरी के बहाने देहरादून सहस्त्रधारा निवासी से लाखों की ठगी

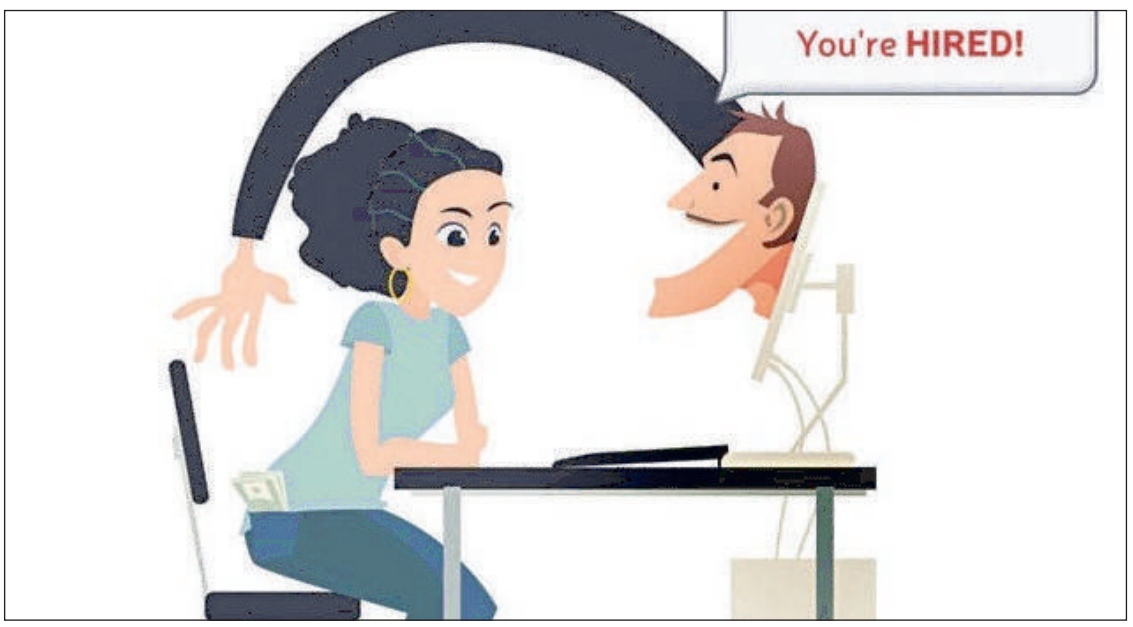

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

चाहे जमीन के नाम पर हो या फ्लैट लेने के नाम पर राजधानी देहरादून में ठगी के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में एक और ठगी सामने आए है। आपको बता दे ऑनलाइन नौकरी के बहाने सहस्त्रधारा निवासी एक व्यक्ति से लाखों की ठगी हुए है। इस संबंध में पीड़िता ने राजपुर थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी के मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है।

बता दे सहस्त्रधारा रोड निवासी जगदीश नायर ने शिकायत दर्ज कराई कि टेलीग्राम एप पर इरा गुप्ता नाम की महिला का फोन आया। महिला ने अपना परिचय रैनस्टैड एचआर कंसल्टेंसी फर्म की कर्मचारी बताया। महिला ने युवक को पार्ट टाइम कमीशन आधारित नौकरी की पेशकश करते हुए कहा कि उसे सभी होटलों का सर्वे करना है। उसे इसमें अच्छा कमीशन मिल सकता है।

साथ ही बताया कि फर्म ज्वाइन करने के नाम पर युवाओं को 10 हजार देने होंगे। जगदीश नायर ने महिला की आड़ में 10 हजार का भुगतान किया। कंपनी ने नौकरी शुरू करने के बाद युवक के खाते में कमीशन के तौर पर 15,700 रुपये ट्रांसफर किए। उसके बाद फर्म की कथित महिला कर्मचारी इरा गुप्ता ने युवक को बहला-फुसलाकर कहा कि आप रैनस्टेड एचआर कंसल्टेंसी फर्म में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वहीं कॉरपोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट में फुल टाइम काम करके अच्छी सैलरी पा सकते हैं।

युवक झांसे में आकर पूर्णकालिक कार्य करने के लिए तैयार हो गया. इसके लिए फर्म की महिला कर्मचारी ने युवक से अलग-अलग बहाने बनाकर रुपए मांगे. महिला के विश्वास में आकर युवक ने अलग-अलग किश्तों में करीब 8 लाख 90 हजार रुपए बताए गए खातों में जमा कर दिए. उसके कुछ दिनों बाद जब युवक का वेतन और कमीशन भुगतान नहीं हुआ तो युवक ने अपने रुपए वापस मांगे लेकिन महिला कर्मचारी का मोबाइल बंद हो गया.थाना राजपुर प्रभारी राजेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया. साथ ही नंबरों की जांच की जा रही है.

20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लगा करंट, 6.5 फीसदी सरचार्ज की पड़ी मार

फ़िरोज़ आलम की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 30 सितंबर , उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बिजली की कीमतों को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहा था। इसके पीछे यूपीसीएल का कहना है कि बिजली के खुले बाजार में दाम बढ़ रहे हैं लिहाज़ा अब यूपीसीएल की सिफारिश पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से 6.5% सरचार्ज बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है.....

मंहगाई के बढ़ते पारे के बीच उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों के इस फैसले से 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने जा रही है. उधर, विपक्षी दल बिजली की कीमतों में बढ़ोत्तरी के ऐसे फैसलों को प्रबंधन की रणनीतिक कमी से जोड़ रहे हैं. खास बात यह है कि इसी वित्त वर्ष की शुरुआत में बिजली के दाम बढ़ाए जा चुके हैं. ऐसे में अब सरचार्ज के नाम पर लोगों की जेब ढीली करने का यह फैसला किसी को भी रास नहीं आ रहा है.

बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी से हालांकि बीपीएल परिवारों को छूट दी गई है लेकिन बाकी उपभोक्ताओं पर 7 महीने तक भारी सरचार्ज वसूलने के आदेश कर दिए गए हैं. इसके बाद अब 100 यूनिट तक पर ₹5 का भार वहन करना होगा, 100 यूनिट से 200 यूनिट तक ₹25 तक अतिरिक्त जमा करने होंगे. 200 से 400 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को करीब ₹55 अतिरिक्त देने होंगे. उधर, इससे ऊपर वाले उपभोक्ताओं को ₹90 तक देने पड़ सकते हैं.

12 नए संक्रमित मिले, दो अक्तूबर तक चलेगा विशेष कोविड टीकाकरण अभियान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जबकि 20 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं, सक्रिय मरीजों की संख्य भी 84 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 1512 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है।

देहरादून में छह, अल्मोड़ा और नैनीताल में दो-दो व पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर में एक-एक संक्रमित मरीज सामने आया है। वहीं, आठ जिलों में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है।

कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में विशेष टीकाकरण अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार ने निशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया था। 30 सितंबर को यह अभियान समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने केंद्र से इस अभियान को दो दिन और बढ़ाने की अनुमति मांगी है। इसके लिए 70 हजार वैक्सीन की डोज राज्य

को दी गई।

कोविड संक्रमण सामान्य होने से अब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए गंभीर नहीं है। जिस कारण राज्य में शत प्रतिशत लोगों को बूस्टर डोज लगाना लक्ष्य से काफी दूर है। अभी तक कुल लाभार्थियों में से 23 प्रतिशत ने बूस्टर डोज लगाई है। जबकि लक्ष्य के सापेक्ष 101 प्रतिशत को पहली और 96 प्रतिशत को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. कुलदीप मर्तोलिया ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में विशेष कोविड टीकाकरण अभियान चलाया गया है। 12 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविशील्ड, कोवॉक्सिन और कार्बिवैक्स वैक्सीन निशुल्क लगाई जा रही है। प्रदेश में यह अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने अनुमति देकर 70 हजार वैक्सीन भी भेजी है।

संपादकीय

इटली में दक्षिणपंथ का उभार

इटली में जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना है. वहां पहले भी धुर दक्षिणपंथी संगठन सक्रिय रहे हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुसोलिनी के समर्थकों ने इटली सोशल मूवमेंट की स्थापना की थी. मेलोनी के गठबंधन में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की राजनीति में भी धुर दक्षिणपंथ के कुछ तत्व देखे जा सकते हैं. गठबंधन के एक अहम नेता मैत्तियो सल्विनी को भी बहुत हद तक धुर दक्षिणपंथ से संबद्ध माना जाता रहा है तथा वे पहले सरकार में रह चुके हैं. तो, दक्षिणपंथ के अलग-अलग रूप पहले से रहे हैं, पर यह पहली बार हो रहा है कि स्पष्ट रूप से धुर दक्षिणपंथी एजेंडे को लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति इटली का प्रधानमंत्री होगा और नयी सरकार के नीतियों पर उसका वर्चस्व होगा. इस कारण अनेक राजनीतिक विश्लेषक यह कह रहे हैं कि मेलोनी की सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन को बनाये रखने की होगी. यह भी उल्लेखनीय है कि मेलोनी अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी. कभी सार्वजनिक रूप से मुसोलिनी की प्रशंसा करने वाली मेलोनी अब अपने को फासीवादी अतीत से अलग करने में लगी हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी सरकार के एजेंडे का स्वरूप कैसा होता है. यूरोपीय संघ के सबसे प्रारंभिक सदस्यों में एक इटली भी है तथा इस समूह को साकार करने में उसकी अहम भूमिका रही है. इटली समेत यूरोप के कुछ अन्य देशों में धुर दक्षिण के उभार से दो मुख्य मुद्दे सामने आते हैं. पहला और सबसे गंभीर मुद्दा यूरोपीय संघ की प्रवासी नीति है. पश्चिमी एशिया के शरणार्थी पहले और अधिक संख्या में इटली ही पहुंचते हैं. रिपोर्टों की मानें, तो इस साल ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में आने वाले शरणार्थियों की संख्या पिछले साल की तुलना में 84 प्रतिशत अधिक है. उल्लेखनीय है कि इटली में भारतीय मूल के लोग भी अच्छी संख्या में हैं, पर उनके बारे में हम लोग बहुत अधिक चर्चा नहीं करते हैं. यूरोप की सभी धुर दक्षिणपंथी पार्टियां और कई दक्षिणपंथी पार्टियां यूरोपीय संघ की आप्रवासन नीति का जोरदार विरोध करती हैं तथा इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ से अलग होने की धमकी भी देती हैं. इस धमकी को गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को अलग करने का जो ब्रेक्जिट अभियान चला था, उसका एक प्रमुख मुद्दा यूरोपीय संघ की प्रवासी नीति थी. ये पार्टियां अपने-अपने देशों में आबादी के बड़े हिस्से को यह समझा पाने में कामयाब रही हैं कि दूसरे देशों से आते लोगों के रेले उनके रोजगार का नुकसान कर रहे हैं, संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं तथा यूरोपीय संस्कृति व जीवनशैली को तबाह कर रहे हैं. धुर दक्षिणपंथ के उभार से दूसरी प्रमुख चिंता यह बढ़ी है कि इससे यूरोपीय एकजुटता को खतरा पैदा हो सकता है. यूरोपीय संघ वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली संगठन माना जाता है. मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली समेत सभी धुर दक्षिणपंथी पार्टियां विभिन्न मामलों को लेकर यूरोपीय संघ पर हमलावर रहती हैं. फ्रांस में पिछले राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करने वाली ला पेन कहती रही हैं कि उन्हें संघ से बाहर जाना है. ब्रिटेन में 2016 में चला ब्रेक्जिट अभियान हमने देखा ही है. पोलैंड और हंगरी में सत्तारूढ़ धुर दक्षिणपंथी सरकारों का यूरोपीय संघ से लगातार टकराव चलता रहता है.

पुलिस ने दर्जनों नशे के इन्जेक्शनो के साथ तीन को किया गिरफ्तार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हल्द्वानी। उत्तराखंड में नशे के कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है,, पुलिस नशा और हुए बेचने वालों का जड़ से सफाया करना चाहती है..इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट के निर्देश पर जनपद नैनीताल में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी के नेतृत्व में गठित पुलिस ने दो अगल अगल मामलों में तीन नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 207 नशीले इंजेक्शन बरामद किये गए है। बनभूलपुरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विगत 28 सितंबर बुधवार को उप निरीक्षक वीरेंद्र चंद्र अपने साथी कांस्टेबलों के साथ क्षेत्र में रात्रि गश्त पर थे, तभी आँवला चौकी गेट के पास एक युवक तीनपानी की ओर से आता हुआ दिखाई दिया, जोकि पुलिस कर्मियों को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिससे पुलिस कर्मियों ने उन्हें पीछाकर दबोच लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम रिज़वान उर्फ बाबू ,उम्र 28 वर्ष पुत्र राशिद मियां निवासी काबुल का बगीचा इंदिरानगर हल्द्वानी बताया। पुलिस ने युवक ने पास से Buprenorphine के 50 नशे के इंजेक्शन व AViL के 52 नशे के इंजेक्शन भी बरामद किये । नशे के इंजेक्शन के संबंध में युवक ने बताया कि वह यह इंजेक्शन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बस स्टैंड से बंटी नामक युवक से लाता है और काठगोदाम क्षेत्र में बेच देता है। पुलिस ने थाना बनभूलपुरा में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत संबंधित धाराओं के तहत अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया।

इधर दूसरे मामले में उप निरीक्षक मनोज यादव अपने साथी कांस्टेबलों के साथ क्षेत्र में रात्रि गश्त पर थे, कि तभी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन बोल्गा होटल वाली गली की ओर से आ रहे दो युवक पुलिस कर्मियों को देखकर भागने लगे, शक होने पर पुलिस कर्मियों दोनों युवकों का भागकर पीछा करके पकड़ा। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम ललित थापा उम्र 20 वर्षपुत्र खड़क सिंह थापा निवासी गौलापार बागजाला काठगोदाम व आशीष उर्फ लल्ला उम्र 22 वर्ष पुत्र राजा राम निवासी वार्ड नं० 14 जाम फेक्ट्री के पीछे जवाहर नगर हल्द्वानी बताया। पुलिस ने दोनों युवकों के पास से Buprenorphine के 58 नशे के इंजेक्शन व AViL के 47 नशे के इंजेक्शन भी बरामद किये । नशे के इंजेक्शन के संबंध में दोनों युवको ने बताया कि वह यह इंजेक्शन अपने दोस्त विशाल गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता निवासी जोशी विहार गोजाजली बताया। पुलिस ने थाना बनभूलपुरा में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत संबंधित धाराओं के तहत दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया है

ग्राम प्रधानों को टीबी रोग आदि बीमारियों के बारे में बताये : युगल किशोर पंत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रूद्रपुर 30 सितम्बर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जिला टी0बी0 फोरम की बैठक आयोजित हुई। उन्होने सीएमओ डा सुनीता चुफाल रतूड़ी को निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विभाग की ब्लाक स्तर की मीटिंग में ग्राम प्रधानो को बुलाये व ग्राम प्रधानो को टीबी रोग आदि बीमारियों के बारे मे बताये जिससे कि जिससे उनके द्वारा गांव के लोगों को भी जागरूक कर सकें। उन्होने कहा कि ग्राम प्रधान, आशा व आंगनबाडी कार्यकत्री आम जनता के बीच में रहते इस लिये इनके द्वारा लोगों को अच्छी तरह से बीमारी से बचाव व ईलाज हेतु जागरूक कर सकते है। उन्होने सीएमओ निर्देश दिये कि आशा व आंगनबाडी के माध्यम से लोगों को जागरूक कराये कि कोई भी बीमारी को छुपाये नही समय से जांच कराये जिससे की बीमारी का पता चल सके और उसका समय से ईलाज करा सके। उन्होने जिला विकास अधिकारी व जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अपने स्तर से भी ग्राम प्रधानो को बीमारी से बचाव व ईलाज के बारे में जागरूक करें। उन्होने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में भी जाकर कार्मिकों को जागरूक किया जाये। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित एनजीओ के पदाधिकारियों व टी0बी0 रोग से स्वस्थ हो चुके लोगों से सुझाव लेते हुये कहा कि अनुभव के अनुसार बीमारी से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करे। इस दौरान टीबी रोग से स्वस्थ होकर लोगों को जागरूक कर रहे रूद्रपुर की आंचल, खटीमा के भीम चन्द एवं काशीपुर के राजीव कुमार टीबी चैम्पियन को सम्मानित किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि टी0बी0 रोग से अपने प्रदेश व देश को मुक्त किया जाये। उन्होने बताया कि प्रत्येक नि-क्षय मित्र द्वारा टी0बी0 के रोगी को गोद लिया जायेगा ताकि उनको बेहतर उपचार, आहार आदि दिया जा सके। उन्होने सीएमओ को निर्देश दिये कि जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों आदि को नि-क्षय मित्र बनाये ताकि सभी के सामूहिक प्रयास से टी0बी0 के रोगियों की बेहतर देखभाल हो सके एवं जनपद को शीघ्र टी0बी0 मुक्त किया जा सके।

सीएमओ डा0 सुनीता चुफाल रतूड़ी ने बताया कि पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक टीबी रोगी का जांच व उपचार निःशुल्क किया जाता है। उन्होने बताया कि असहाय व स्वास्थ्य केन्द्र आने में असमर्थ मरीज किसी भी प्रकार की जानकारी व बलगम परीक्षण की सुविधा के लिये सम्बन्धित क्षेत्र के टीबी सुपरवाईजर से सम्पर्क कर सकते है एवं टोल फ्री नम्बर 104 पर काल कर जानकारी ले सकते है। उन्होने बताया कि जनपद में अब तक 281 नि-क्षय मित्र बनाये जा चुके है इसी के साथ प्रदेश में नि-क्षय मित्र बनाने में जनपद प्रथम स्थान पर है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि अतुल जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 सुनीता चुफाल रतूड़ी, प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर डॉ0 के एस शाही, जिला विकास अधिकारी तारा हयांकी, मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी आर्या, एसीएमओ डा0 हरेन्द्र मलिक, डा0 मंदीप सिंह, डॉ0 राजीव सेतिया, औद्योगिक संस्थान से विशाल गर्ग सहित एनजीओ के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

'स्पीड' का शिकार हुई घायल महिला अस्पताल में भर्ती

रिपोर्ट: एम. फहीम 'तन्हा'
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। दून की सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। तेज़ रफ़्तार मोटरसाईकिल से टक्कर में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसका मैक्स होस्पिटल में इलाज चल रहा है। महिला के दोनों हाथों में गंभीर रूप से जख्म और चोट आई हैं। ये घटना मंगलवार की शाम की है लेकिन इसका cctv वीडियो गुरुवार को सामने आया तो इस दुर्घटना की गंभीरता का खुलासा हुआ। देहरादून की कॉलोनी वाली और कम ट्रैफिक वाली सड़कों पर हादसे सामने आते रहते हैं, अब इस घटना ने फिर से तेज़ रफ़्तार पर नियंत्रण का प्रश्न खड़ा कर दिया है।प्राप्त प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र डालनवाला के अंतर्गत आराघर पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले गुरुतेग बहादुर रोड मॉडल कॉलोनी की लेन नंबर 3 की निवासी श्रीमती रेनू जाट मंगलवार 27 सितंबर की शाम को करीब सवा पांच बजे घर के बाहर की सड़क पार करके दूध लेकर लौट रहीं थीं। तभी आईबीएम टावर की तरफ से तेज़ गति से आ रही मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि रेनू जाट हवा में उछलकर मोटरसाइकल के आगे हिस्से में फंसाकर काफी दूर जाकर गिरीं। सामने गली में उनके मकान मालिक लक्ष्मीकांत गोदियाल, पड़ोसी बीआर पोखरियाल और एसपी गुप्ता ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला के पति शक्ति सिंह ने बताया कि वे घटना के समय नजीबाबाद गए हुए थे, एक्सीडेंट होने पर मौके पर पहुंचे पड़ोसी ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी लेकिन काफी देर होने के कारण वे स्वयं ही अस्पताल ले गए। उनका कहना है कि मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती उनकी पत्नी की आज गुरुवार को सर्जरी हुई है। उन्होंने आरघार चौकी में घटना की तहरीर देकर मोटसाइकिल चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि घटना के दूसरे दिन गुरुवार को व्यक्तिगत प्रयासों से ही कॉलोनी में लगे सीसीटीव कैमरों की फुटेज तलाश की गईं जिससे घटना का सही से पता चल सका, पुलिस से अनुरोध है कि cctv फुटेज का परीक्षण करके दोषी पर कार्यवाही होनी चाहिए। आराघर पुलिस चौकी प्रभारी पंकज महिपाल का कहना है कि घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज के अलावा आसपास के cctv भी चेक किये जा रहे हैं। जिनके माध्यम से पहचान करके कार्यवाही की जाएगी। चौकी प्रभारी ने तेज़ रफ़्तार से मोटरसाइकिल चलाने वालों पर कार्यवाही की बात कही है।

तेज़ रफ़्तार टू-व्हीलर्स की चपेट में आकर इससे पहले कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा और जाने माने फोटो जर्नलिस्ट विनोद पुंडीर भी शहर की अलग अलग सड़कों पर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, और दोनों अभी भी बेडरेस्ट पर चल रहे हैं। गुरुतेग बहादुर रोड पर हुई इस ताज़ी घटना ने कॉलोनियों की सड़कों पर तेज़ रफ़्तार से चलने वाले वाहन चालको पर नियंत्रण का सवाल खड़ा कर दिया है। राजधानी की ट्रैफिक पुलिस दिनभर नो-पार्किंग या सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की रसीद काटते हैं। लेकिन गली मोहल्लों और कॉलोनियों में तेज रफ्तार वालों पर अंकुश कैसे लगेगा इसपर लगता है किसी का ध्यान नहीं है।आरघार चौक से डॉ. आरएन सिंह के क्लिनिक से शुरू होने वाली गुरुतेग बहादुर रोड इन दिनों धर्मपुर वाली मुख्य सड़क का बाईपास रोड बना हुआ है। ये रोड मॉडल कॉलोनी के अंदर से होते हुए ibm टॉवर से नेहरू कॉलोनी चौक पर निकलती है। ईसी रोड से हरिद्वार रोड की तरफ जाने वाले बहुत से वाहन अब आराघर से इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दिनभर इस सड़क पर गाड़ियों का आवागमन होने लगा है, बहुत से वाहन आरघार-धर्मपुर में पुलिस पिकेट से बचने के लिए इस कॉलोनी की इस बाईपास सड़क का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दुर्घटना भी होने लगी है। इस तरफ भी पुलिस को ध्यान देना चाहिए ताकि और किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके।

धरासू बैंड के पास गंगोत्री हाईवे पर शुरू हुई वाहनों की आवाजाही, यमुनोत्री अब भी बंद

न्यूज वायरस नेटवर्क

धरासू बैंड के पास भारी भूस्खलन से बंद गंगोत्री हाईवे पर बृहस्पतिवार को आवाजाही शुरू हो गई जबकि यमुनोत्री हाईवे अब भी बंद है। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। बीते बुधवार शाम करीब छह बजे धरासू बैंड के पास यमुनोत्री हाईवे पर अचानक भूस्खलन शुरू हुआ।

इससे हाईवे के नीचे से गुजर रहा गंगोत्री मार्ग भी मलबा गिरने से बंद हो गया। बृहस्पतिवार सुबह बीआरओ ने गंगोत्री हाईवे पर मलबा हटाने का काम शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही सुचारू हो पाई। वहीं यमुनोत्री हाईवे अब भी बंद है। हाईवे खोलने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से गंगोत्री हाईवे पर आवागमन को कुछ समय बंद रखा जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन

अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि यमुनोत्री हाईवे पर भी जल्द आवाजाही सुचारु की जाएगी। मोरी विकासखंड के सौड़-तालुका-ओसला निर्माणाधीन मोटर मार्ग पर चट्टान से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग को हायर सेंटर रेफर किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क कटिंग के लिए विस्फोटकों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे चट्टानों पर फंसे पत्थर लगातार गिर रहे हैं।

मोरी विकासखंड में पीएमजीएसवाई की ओर से सौड़-तालुका- ओसला मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क कटिंग के लिए पीएमजीएसवाई विस्फोटक का प्रयोग कर रहे हैं। विस्फोट के बाद चट्टानों पर फंसे पत्थरों को निकालने के बजाय छोड़ दिया जा रहा है।

बृहस्पतिवार को निर्माणाधीन मोटर मार्ग पर सांकरी की ओर पैदल जा रहे गंगाड़ गांव निवासी फूलक सिंह घींया गाड़ के समीप चट्टान से अचानक गिरे पत्थर की चपेट में आ गए। फूलक सिंह के पुत्र चैन सिंह ने बताया कि पत्थर लगने से उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई है। फूलक सिंह को सीएचसी मोरी में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता पीडीएस लिंगवाल ने बताया कि मोटर मार्ग निर्माण में विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिस स्थान पर घटना हुई है वहां कठोर चट्टानें हैं। पत्थर गिरने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा।

दैनिक
न्यूज वायरस
न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।
सम्पादक:
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष: 0135-2672002
email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा